आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक–25 जुलाई 2024 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- रेलवे के विकास के लिए बजट में प्रदेश को उन्नीस हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़ रुपये किये गये आवंटित।
- अब अपनी तैनाती तहसील में ही निवास करेंगे एसडीएम और तहसीलदार। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जारी किया आदेश।
- सर्वोच्च न्यायालय में उन्तीस जुलाई से तीन अगस्त तक आयोजित होगी विशेष लोक अदालत।
- बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने की तैयारियां पूरी। सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिये दस प्रतिशत आरक्षण और आयु में मिलेगी छूट।

****

केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए कुल बानबे हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दो हजार चार से दो हजार चौदह तक यूपीए के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए ग्यारह सौ नौ करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर उन्नीस हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़ रूपये कर दिया गया है, जो पिछली सरकार की तुलना में अट्ठारह गुना ज्यादा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए उन्नीस हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। जिस तेजी से पिछले दस वर्षों में उत्तर प्रदेश में रेलवे का काम हुआ है उसका आप किसी भी पैमाने पे देखे तो वो एक नया रिकार्ड है।

श्री वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों में चार हजार नौ सौ किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की लंबाई से अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे ट्रैक का सौ प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। साथ ही प्रदेश में पिछले दस वर्षों में चौदह सौ नब्बे फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुगम हुआ है और दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए चालीस से अधिक प्रोजेक्ट्स को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का पुर्नविकास कई चरणों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कुंभ की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं। कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। उधर पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट का अधिकांश हिस्सा रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनो की आमने–सामने टक्कर रोकने वाली प्रणाली कवच को मंजूरी मिल चुकी है। इसे इस्टांल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए पहले ऑप्टीकल फाइबर बिछा कर नेटवर्क को कनेक्ट करना जरूरी है। जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। मीटर गेज लाईनों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया है। तीसरी लाईन के निर्माण और दोहरीकरण के कार्य में तेजी आयी है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्वविकास का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है।

****

राज्यसभा में कल शून्यकाल के दौरान केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। कल सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केन्द्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास था।

उधर, लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। अध्यक्ष ओम बिडला ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सदन को शून्यकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना सही नहीं है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं ने सदन की सुचारू कार्यवाही चलाने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन उपयुक्त नहीं है।

****

जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए अब सभी एसडीएम और तहसीलदार को अपनी तहसील में ही निवास करना होगा। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता से कार्य करें। साथ ही सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर सात दिन के अन्दर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं।

****

सीमा सुरक्षा बल– बीएसएफ, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल– सीआईएसएफ और रेलवे सुरक्षा बल– आरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को अपने–अपने संगठन में शामिल करने की तैयारियां कर ली हैं। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को सीमासुरक्षा बल में भर्ती के लिए दस प्रतिशत आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने भी कहा कि पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर दस प्रतिशत आरक्षण, आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल, आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट के साथ पूर्व अग्निवीरों का बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

****

लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय उन्तीस जुलाई से तीन अगस्त दो हजार चौबीस तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है, जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं।

इस साल 29 जुलाई से तीन अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, व्यक्तिगण से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स इन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं उनमें क्या हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं।

उधर, सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की कार्य अवधि से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार नई कार्य अवधि सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी। शीर्ष न्यायालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि छुट्टियों और दूसरे तथा चौथे शनिवार को अदालत के कार्यालय बंद रहेंगे। नए नियम एक अगस्त से लागू होंगे।

****

सर्वोच्च न्यायालय के नीट–यूजी परीक्षा–दो हजार चौबीस दोबारा न कराने के आदेश के बाद देशभर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए कल से कॉउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। शीर्ष न्यायालय के फैसले पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा एजेंसी को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। श्री प्रधान ने कहा कि समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्र की है और विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये की निंदा की है।

****

प्रयागराज महाकुंभ मेले की तैयारी बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आगामी महाकुंभ दो हजार पच्चीस, क्लीन और ग्रीन होना चाहिए। मेला क्षेत्र में स्थापित शौचालय साफ होने चाहिए। उनकी सफाई की निगरानी थर्ड पार्टी को दी जाय,यह सुनिश्चित किया जाय कि दूषित जल गंगा में प्रवाहित न होने पाए। उन्होंने कहा कि शहर के परिदृश्य को नया रूप देने के लिये भित्तीचित्र, साइनेज और जगह–जगह स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ ही जंक्शन को भी सजाया जाए।

****

भारत–पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तेइस जुलाई को हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सुभाष चन्द्र का पार्थिव शरीर आज उनके हाथरस स्थित सादाबाद तहसील के नागलमनी गांव लाया जायेगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव में ही शहीद का अन्तिम संस्कार होगा।

****